पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 19, अंक 4/2018

सामुदायिक साझेदारी से सतत् विकास संभव

'सामुदायिक साझेदारी को अगर दैनिक जीवन में उतारा जाए तो यह सतत् एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी'। उक्त विचार जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल ने 'कट्स' द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में रखे।

खण्डेलवाल ने कहा कि हमारे जीवन में साझा करने की परम्परा शुरु से ही रही है, अगर हम इसे अपना लेते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा, साथ ही साथ जन समुदाय में साझेदारी की भावना भी जागृत होगी। हमारे यहां 'शेयरिंग परंपरा' में महिलाएं सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाती हैं और ये उपयोग में ली गई अधिकांश वस्तुओं का पुनः उपयोग भी करती हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में निष्कासित अथवा उपयोग में ली जा चुकी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कचरे के रूप में संग्रहित होती है, जिसके फलस्वरूप संग्रहित कचरा एक बड़े आकार के ढेर में परिवर्तित होता रहता है। इसी ढेर को पुनःचक्रिय पद्धति से निस्तारित कर किसी अन्य उपयोग में ले सकने की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। इससे 'एक पंथ दो काज' का सिद्धांत लागू हो सकेगा।

परिचर्चा का आयोजन 'कट्स' द्वारा संचालित परियोजना 'ग्रीन एक्शन वीक–2018' की इस वर्ष की थीम 'शेयरिंग

कम्यूनिटी' के तहत किया गया। परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि साझेदारी की भावना हमारे पूर्वजों में विद्यमान थी, परन्तु धीरे–धीरे हम इसे खोते जा रहे हैं। शेयरिंग कम्यूनिटी की थीम पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम समाज में साझेदारी की भावना को जागृत कर सकते हैं। जैसे कार पूलिंग, पुस्तकों व कपड़ों की आपस में शेयरिंग आदि–आदि।

चेरियन ने संयुक्त राष्ट्र के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार 1999 में सतत् उपयोग के शामिल होने के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए वस्तुओं को उपयोग में लेने और अन्ततः कम से कम प्रदूषण और अपशिष्ट सृजित होने की बात कही गई है।

'कट्स' की कार्यक्रम अधिकारी निमिषा शर्मा ने बताया कि ग्रीन एक्शन वीक–2018 के दौरान जयपुर शहर में रामनगर व मीनावाला में 50 परिवारों के साथ काम करके उनके घरों पर किचन गार्डन बनवाए गए तथा उन परिवारों में से 10 के यहां कम्पोस्ट यूनिट लगवाकर रसोई से निकलने वाले कचरे से खाद बनवाई गई।

परिचर्चा में विकास सीतारामजी भाले, कृषि आयुक्त, राजस्थान सरकार ने जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि यह सतत् विकास को बढ़ावा देने का एक जरिया है, जिसमें बीजों का आदान–प्रदान करके हम पुराने जैविक बीजों को विकसित कर सकते हैं। इससे किसान वर्ग में साझेदारी की भावना का विकास होगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सोमना दत्ता ने शेयरिंग कम्यूनिटी थीम पर प्रकाश डालते हुए इसके विभिन्न तरीकों के बारे में अवगत कराया जो सतत् विकास की जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं।

कार्यक्रम में 'कट्स' द्वारा प्रकाशित भारत में सतत् उपभोग संस्कृति एवं जीवन शैली से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधियों तथा किसानों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

इस अंक में...

- सरकारी बैंकों का घाटा साढ़े तीन गुना बढ़ा 3
- नोटबंदी से कालेधन पर रोक की खुली पोल ... 5
- प्रदेश में किसानों के कर्ज हुए माफ 7
- पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं लोग 9
- कृषि योजनाओं में महिलाएं हों लाभार्थी 10

प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था से उपभोक्ता को मिले त्वरित न्याय

वर्तमान न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में उपभोक्ता परिवादों का समय पर निस्तारण नहीं होने से उपभोक्ता परेशान और शोषित होता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संगठनों, जागरूक कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर त्वरित न्याय प्रणाली की मांग करनी होगी।

उक्त विचार जिला रसद कार्यालय एवं 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय विचार गोष्ठी में 'उपभोक्ता परिवादों का समय पर निस्तारण' विषयक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनिल कुमार झा ने व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक शिव राम चौधरी ने बताया कि उपभोक्ता जब खाद्य वस्तुओं का क्रय करे तब विशेष रूप से एगमार्क या प्लस फोर्टीफाइड जैसे मानकों के उत्पाद ही खरीदें। उन्होंने बताया कि जागरूकता के अभाव में कई बार उपभोक्ता अवधिपार खाद्य सामग्री खरीद लेता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश तोषनीवाल ने कहा कि उपभोक्ता परिवादों के समय पर निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत उचित प्रारूप में पूरा विवरण देते हुए प्रस्तुत करनी चाहिए। शिकायत का निरन्तर फॉलोअप करने से शिकायत का निवारण समय पर हो सकेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के समन्वयक गौहर महमूद ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि उपभोक्ता को शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी देने और उन्हें उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है।

विचार गोष्ठी में प्रतिभागियों ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं में उपभोक्ता अधिनियम और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर डॉ. बी.एस.तंवर, सामाजिक कार्यकर्ता गंगाधर सोलंकी, रामनारायण जाट, मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रीति तनेजा, पार्षद रामचन्द्र गुर्जर, रोशन मेवाड़ी, संपतराम लढ्ढा, नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, एडवोकेट नारायण लाल गुर्जर, लीलाकंवर चौहान तथा भूपेन्द्र सिंह झाला ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

बैंकिंग जानकारी देने के साथ बताई योजनाएं

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 'कट्स' द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत सम्पर्क संस्थान कुचामन सिटी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सम्पर्क संस्थान की सचिव सुशीला चौहान ने वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि रिजर्व बैंक की इस योजना के तहत ग्राहकों को बैंकिंग कार्य प्रणाली, शिकायत निवारण प्रक्रिया एवं बैंकिंग धोखाधड़ी के प्रति सावधानी बरतने जैसी जानकारियां देकर उन्हें जागरूक बनाया जा रहा है।

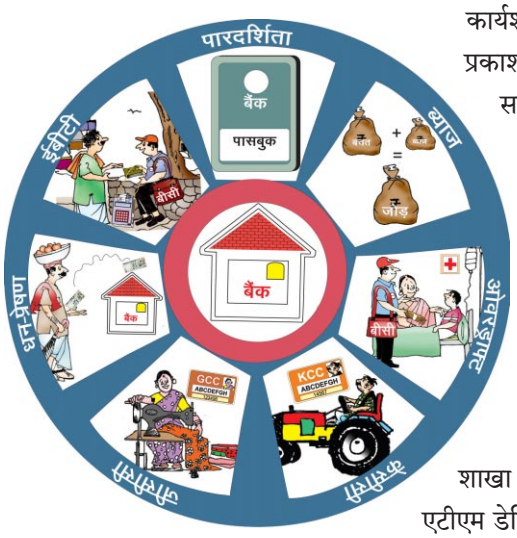

कार्यशाला के प्रारंभ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बचत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बैंकों की विभिन्न बचत योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बैंकों में हो रहे साईबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए बैंक ग्राहकों को इससे बचने के उपाय सुझाए। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा भीलवाड़ा के एफएलसी कोर्डिनेटर पुखराज नाहर ने बैंक से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक रवि ने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ग्राहकों को बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति सावचेत किया। वहीं यूकों बैंक के सहायक प्रबन्धक विवेक शर्मा ने नेट बैंकिंग के एप और डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताया और इससे संबंधित फिल्म भी दिखाई।

कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक प्रबंधक मनीष चौहान एवं बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक अनुपम शर्मा ने एटीएम पिन की सुरक्षा तथा बैंकिंग निवेश की जानकारी देते हुए एटीएम डेबिट कार्ड से कैसे धोखाधड़ी हो सकती है उसे फिल्म के माध्यम से दर्शाते हुए प्रतिभागियों को सावधानी बरतने की सीख दी। लॉक साक्षरता समन्वयक चम्पालाल कुमावत ने साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत किए जाने वाले बैंक लेन-देन तथा व्यवहारों से संबंधित विभिन्न कठिनाइयों से अवगत करवाते हुए कहा कि बैंक कर्मियों को रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ग्राहकों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए, तभी वित्तीय साक्षरता के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा। कार्यशाला में करीब 60 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

भुखमरी से पीड़ित देशों में भारत महान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुखमरी पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक भुखमरी से पीड़ित देशों में भारत का नाम भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार तथा अधिक पैदावार के लिए कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान के बावजूद भारत में भुखमरी के हालात बदतर होते जा रहे हैं।

दुनियाभर के देशों में भुखमरी के हालात का विश्लेषण करने वाली गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले साल भारत दुनिया के 119 देशों के हंगर इंडेक्स में 97 वें स्थान पर था। जो इस साल फिसलकर 100वें स्थान पर आ गया है। शर्मनाक यह है कि भारत ने सस्ते अनाज की वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने को लेकर कुछ ठोस काम नहीं किया। *(न.नु., 20.10.18)*

किसानों को कर्ज देने से बचते हैं बैंक

कृषि कर्जमाफी से जहां बैंकों की वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ने की बात कही जा रही है, वहीं किसानों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कर्जमाफी के बाद फंड की कमी से बैंक किसानों को कर्ज देना कम कर देते हैं।

कर्जमाफी की घोषणा के बाद सरकार जब तक बैंकों के पैसे लौटा नहीं देती, तब तक बैंक कृषि ऋण के आवंटन को काफी सीमित रखते हैं। आमतौर पर कर्जमाफी का हिसाब-किताब पूरा होने में कई वर्ष लग जाते हैं। यह देरी किसानों के लिए पूंजी की आपूर्ति को धीमा कर देती है। इस वजह से बहुत से किसानों को नॉन बैंकिंग कंपनियों या अन्य स्त्रोतों से ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। *(रा.प., 22.12.18)*

अमीरों व गरीबों के बीच बढ़ती खाई

देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ती जा रही है। एक तबके के पास विलासिता के लिए खूब धन उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसना पड़ता है। देश में पूंजीपतियों की आय में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

दूसरी तरफ बड़ी आबादी को दो जून रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जबकि वंचित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होना चाहिए। ग्रामीण गरीब परिवारों की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। रोजगार की कमी से वे मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। जबकि जरूरत ग्रामीण भारत को विकास की मुख्य धारा से जोड़े जाने की होनी चाहिए। *(दै.न., 22.10.18)*

समग्र विकास की नहीं बनी योजना

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की प्लानिंग नहीं होने के कारण समग्र ग्राम विकास का पैसा खर्च नहीं हो पाया है। योजना के तहत पांच साल में (2012 से 2017) 21.81 फीसदी पैसा ही खर्च हो सका है।

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का उद्देश्य पांच जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद की 14 पंचायत समितियों में सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत विकास करना था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियों के चलते उपलब्ध 202.34 करोड़ की निधियों में से केवल 21.81 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 90.29 करोड़ रुपए बिना खर्च शेष रहा। *(दै.न., 02.10.18)*

उर्वरकों ने बिगाड़ा मृदा का स्वास्थ्य

प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हो रहे रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से करीब 75 प्रतिशत मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इससे मृदा में सूक्ष्म तत्वों की लगातार कमी हो रही है। जिसका बुरा असर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर पड़ रहा है। किसानों को अपने स्वास्थ्य की तरह मृदा के स्वास्थ्य का भी खयाल रखना चाहिए।

यह बात जयपुर स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में आयोजित एक कार्यशाला में उभर कर सामने आई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि परीक्षण में 40 प्रतिशत मृदा में सल्फर और 50 प्रतिशत में जस्ते की कमी पाई गई है। किसानों को देशी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। *(रा.प., 01.11.18)*

जलदाय विभाग ने दबाई फाइल

जलदाय विभाग के इंजीनियर व ठेकेदार मिलकर पेयजल स्कीम में धड़ल्ले से घटिया पाइप और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। विभाग के हिंडौन सिटी के बाद सवाई माधोपुर डिविजन में लगे करोड़ों रुपए के पाइपों के छह सैंपल की नेशनल टैस्ट हाउस लैब में जांच करवाई।

यहां पर पांच सैंपल एक साल पहले ही फेल हो गए। इसकी पांच करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत बताई जा रही है। विभाग में जांच के लिए विजिलेंस विंग व क्वालिटी कंट्रोल विंग बना रखी है। लेकिन जांच रिपोर्ट व कार्रवाई की सिफारिश को अधिकारियों ने फाइलों में दबा कर रख दी है। *(दै.भा., 26.12.18)*

सरकारी बैंकों का घाटा साढ़े तीन गुना बढ़ा

बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तमाम सरकारी दावों के बावजूद सरकारी बैंकों की हालत सुधरती नहीं दिख रही है। जुलाई-सितम्बर तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का घाटा करीब साढ़े तीन गुना बढ़कर 14,716.2 करोड़ रुपए रहा। इसका कारण बैंकों के फंसे कर्ज में बढ़ोतरी होना है।

सालाना आधार पर तुलना की जाए तो देश के 21 सरकारी बैंकों के घाटे में भारी बढ़ोतरी साफ नजर आती है। क्योंकि, पिछले वित्त वर्ष 2017-18 की इसी तिमाही में बैंकों का घाटा 4,284.45 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि नतीजों को तिमाही आधार पर देखने पर स्थिति कुछ सुधरी नजर आती है, क्योंकि बीती तिमाही का घाटा उससे पहले की अप्रेल-जून तिमाही के मुकाबले लगभग 2,000 करोड़ रुपए कम रहा। अप्रेल-जून में सरकारी बैंकों का घाटा 16,614.9 करोड़ रुपए रहा था। सबसे तगड़ा झटका पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लगा। सुधार के दावों के बावजूद डूबे कर्जे की फांस काफी चिंताजनक हैं। *(रा.प., 19.11.18)*

गरीबों का आधार नहीं हुआ लिंक : कैसे मिलेगा लाभ

देशभर में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी) के तहत पंजीकृत आधे से ज्यादा गरीबों के आधार विवरणों का सत्यापन न होने की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा।

सामाजिक सहायता कार्यक्रम में कुल 2.84 करोड़ में से अब तक मात्र 1.92 करोड़ गरीबों के आधार विवरण दर्ज (सीडिंग) हो सके हैं। इनमें से मात्र 1.02 करोड़ लोगों के विवरणों का सत्यापन हो सका है। यानी कुल 2.84 करोड़ जरूरतमंद गरीबों में से 1.82 करोड़ ऐसे हैं जिनके आधार विवरण कार्ड या तो दर्ज नहीं या उनके विवरणों की पुष्टि नहीं हो सकी। यह खुलासा केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा के एक पत्र से हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन आंकड़ों का हवाला देते हुए लाभार्थियों के आधार नंबरों का सत्यापन युद्ध स्तर पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। *(रा.प., 12.11.18)*

आरटीआई: कमजोर करने की साजिश

सूचना के अधिकार कानून के कमजोर करने के आरोपों के बीच केंद्रीय सूचना आयोग के खिलाफ मुकदमें, खालीपद और लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ने पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय केंद्रीय सूचना आयोग समेत देश के कई आयोगों में पद खाली हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में अभी सिर्फ चार सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त समेत सात पद खाली हैं। कई राज्यों के सूचना आयोग में भी कई पद खाली हैं। इससे लंबित अपील और शिकायतों का अंबार लग रहा है।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (सीएचआरआई) के मुताबिक देशभर में सूचना आयोग के कुल 146 पदों में से 100 से भी ज्यादा पद खाली हैं। इनमें कई आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त तक नहीं हैं। देश के 19 आयोगों में दो लाख के करीब द्वितीय अपील और शिकायतों के मामले लंबित है। सूचना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 35 प्रतिशत सरकारी विभाग जनता को सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। *(रा.प., 07.12.18)*

बिना अनुमति किया करोड़ों का खर्च

केंद्र सरकार हर साल एड्स पीड़ितों के लिए चिकित्सा विभाग के अधीन चलने वाली राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को 20 से 25 करोड़ रुपए देती है। सोसायटी को हर साल एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह तय करना होता है कि यह फंड किस मद में खर्च होगा।

केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य में एक एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई। इसकी हर साल बैठक होना अनिवार्य है। इसमें एक प्रमुख शासन सचिव, निदेशक, एड्स का एक पॉजीटिव मरीज और एक एनजीओ सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन सोसायटी ने पांच साल में एक भी मीटिंग नहीं की और अफसरों ने अपने हिसाब से इस रकम को खर्च कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि पांच साल में 150 करोड़ रुपए कहां खर्च किए, तो वह जवाब देने से बचते रहे। अब यह शिकायत दिल्ली पहुंच गई है। *(दै.भा., 12.10.18)*

36 देशों में मेडिकल घोटाला

घुटनों का बदलना, कुल्हों को बदलना, हड्डी फ्रैक्चर के दौरान रॉड डालना। इसी तरह के कई चिकित्सीय उपकरण लोगों को राहत देने में विफल रहे हैं। दस में से 2 मामलों में शरीर में लगने वाले चिकित्सकीय उपकरण ठीक से नहीं लगाए जाते। यह खुलासा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने किया है। आइसीआइजे ने भारत सहित 36 देशों से आंकड़े जुटाए हैं।

आइसीआइजे के मुताबिक प्रत्यारोपण के लिए प्रयोग में लाई जा रही ज्यादातर मशीनें विज्ञापन पर आधारित होती है। इनका बीमारी पर कोई खास असर नहीं पड़ता और परेशानी बनी रहती है। कंपनियां इनके विज्ञापन पर बेतहाशा रुपया बहाती है। इन उपकरणों को लगाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। यही कारण है कि कंपनियां इन डॉक्टरों को मोटी रकम घूस के रूप में देती है जिसमें नकदी और तोहफे शामिल हैं। *(रा.प., 27.11.18)*

सांसद निधि पर भारी उदासीनता

सांसद निधि योजना के तहत हर सांसद को प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपए का आवंटन होता है, जिससे वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित विकास के काम करवा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16वीं लोकसभा के 543 में से केवल 35 सांसद ही उन्हें पांच वर्षों में आवंटित 25 करोड़ रुपए की राशि को अपने क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सके।

इसका अर्थ यह हुआ कि बाकी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए इस निधि से जो अतिरिक्त कार्य हो सकते थे। इससे उनके क्षेत्र के आमजन इस लाभ से महरूम रह गए। यह योजना क्रियान्वयन की विफलता और जन प्रतिनिधियों की उदासीनता को उजागर करती है। *(रा.प., 27.12.18)*

बेरोजगारी है सबसे बड़ी समस्या

प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यह ग्राम गदर जनमत सर्वेक्षण 2018 में सामने आया है। राज्य की मुख्य समस्याओं के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में करीब 53 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी की समस्या को सबसे बड़ा बताया। उनका मानना है कि यह समस्या तेजी से बदतर होती जा रही है। सर्वे में अपने विचार व्यक्त करते हुए भीलवाड़ा जिले के प्रेम कुमार बलाई ने प्रदेश में आने वाली नई सरकार से अपेक्षा की है कि वह अपने वादों पर कायम रहे और बेरोजगारी की समस्या को दूर करे। इसी से आमजन का भला हो सकेगा।

बांरा से सुलोचना देवी ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार के पास इसके आंकड़े तक नहीं हैं। नई सरकार को रोजगार बढ़ाने के मौके बनाने होंगे। इसी तरह सर्वे में लोगों ने नई सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए अपने-अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए है।

कारोबार में रिश्वतखोरी कायम

उभरते बाजारों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार अभी कायम है। विकसित बाजारों की तुलना में उभरते बाजारों में भ्रष्टाचार दोगुना है। ईवाई फॉरेंसिक एंड इंटीग्रिटी सर्विसेज द्वारा की गई एक ताजा अध्ययन रिपोर्ट में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है।

ईवाई की उभरते बाजार-ईमानदारी चर्चा 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजारों के आधे से ज्यादा यानी 52 प्रतिशत कार्यकारियों ने कहा है कि कारोबार में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला हुआ है। वहीं भारत में 40 प्रतिशत कार्यकारियों ने यही बात कही। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 प्रतिशत कार्यकारियों का कहना था कि व्यापार में घूसखोरी और भ्रष्टाचार काफी गहराई तक फैला हुआ है। 12 प्रतिशत ने कहा कि कंपनियों को पिछले दो साल के दौरान धोखाधड़ी के मामलों का सामना करना पड़ा। *(न.नु., 03.11.18)*

खरबों डॉलर रिश्वत में दिए गए

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि प्रति वर्ष भ्रष्टाचार के जरिए खरबों डॉलर की चोरी होती है अथवा यह राशि रिश्वत के रूप में दी जाती है। यह राशि वैश्विक जीडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस पर भ्रष्टाचार को संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों पर प्रहार बताया। हर साल नौ दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुतारेस ने कहा 'भ्रष्टाचार स्कूलों, अस्पतालों तथा समाज की अन्य अहम सेवाओं पर प्रहार करता है। विदेशी निवेश को विमुख करता है और देश को प्राकृतिक संसाधनों से विहीन करता है।'

(न.नु., 12.12.18)

पकड़ती है एसीबी, बचाते हैं अधिकारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) प्रयास कर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को पकड़ती है और विभागीय अधिकारी उन्हें बचा लेते हैं। ब्यूरो की जांच में जिन मामलों में आरोप साबित हो गए उनमें भी विभाग ने कार्रवाई कोर्ट तक नहीं पहुंचने दी। विभिन्न विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने ढ़ाई साल में ऐसे डेढ़ सौ से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाया है। इसमें यूडीएच विभाग सबसे ऊपर है।

संबंधित बोर्ड या सक्षम अधिकारी आरोपी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन चलाने की इजाजत नहीं देता। इसके चलते मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता। इस कानून के कारण एसीबी भी लाचार है। ढ़ाई साल में 153 अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद भी अभियोजन के लिए इजाजत नहीं मिली। *(रा.प., 10.11.18)*

जानकारी देने से पीएमओ का इनकार

मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के आदेश के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय (पीएमओ) ने कालेधन व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। सीआईसी ने 16 अक्टूबर को अपने आदेश में पीएमओ से 15 दिनों के भीतर यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था।

सूचना के अधिकार के तहत संजीव चतुर्वेदी के आरटीआई आवेदन पर सीआईसी ने पीएमओ से उक्त सूचनाएं देने को कहा था। लेकिन पीएमओ ने आरटीआई की धारा 8(1)(एच) का हवाला देते हुए विवरण साझा करने से इनकार कर दिया। इस प्रावधान के तहत ऐसी सूचनाएं देने से इनकार किया जा सकता है, जिनके सार्वजनिक होने से किसी मामले में जांच या अभियोजन में बाधा आ सकती है। *(रा.प., 26.11.18)*

विशेष अदालतों में जाएंगे बेनामी सौदें

बेनामी सौदों से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेशन कोर्ट नोटिफाई कर दी है। बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून 1988 के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ परामर्श के बाद यह सेशन कोर्ट नोटिफाई की गई हैं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हर जिले में एडिशनल सेशन जज-2 की अदालत को विशेष अदालत बनाया गया है। बेनामी संपत्ति कानून में कहा गया है कि हर मुकदमें की सुनवाई जितनी तेजी से संभव हो, की जाए। *(दै.भा., 22.10.18)*

बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से है परेशानी

देश के लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ज्यादा परेशान करते हैं। यह जानकारी इप्सोस संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आई है। सर्वे के अनुसार 44 फीसदी भारतीय इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक अपराध व हिंसा से 33 प्रतिशत लोग परेशान हैं। गरीबी और सामाजिक असमानता को 31 फीसदी भारतीय प्रमुख मुद्दा मानते हैं। इसी तरह आतंकवाद को भी 21 फीसदी लोगों ने परेशानी का विषय माना है। इस्पोस का यह सर्वेक्षण एक मासिक सर्वेक्षण है। *(न.नु., 15.10.18)*

नोटबंदी से कालेधन पर रोक की खुली पोल

नवंबर 2016 में नोटबंदी के फैसले से कालेधन पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के दावे की पोल खुल गई है। दरअसल राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों के चुनाव में राजनीतिक दलों ने कालाधन पानी की तरह बहाया। चुनाव आयोग की टीम ने करोड़ों रुपए का सामान पकड़ा, जो पांच साल पहले इन राज्यों के चुनाव में पकड़ी गई नकदी, सोना-चांदी और दूसरे सामान की कीमत से कई गुना ज्यादा हैं।

मसलन, वर्ष 2013 के चुनाव में राजस्थान में नकदी, जेवरात, शराब और नशीले पदार्थ समेत 54 करोड़ रुपए का सामान जब्त हुआ था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नकदी और शराब आदि सहित 23 करोड़ रुपए का सामान बरामद हुआ था। जबकि मौजूदा चुनाव में कुल 86.46 करोड़ रुपए के सामान की जब्ती हुई जो राजस्थान में पिछले चुनाव से करीब 32 करोड़ रुपए ज्यादा है। *(रा.प., 11.12.18)*

नकद के अलावा अन्य तरीके से दी रिश्वत

सर्वे के अनुसार केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था में नकदी खत्म करने और 'कैशलेस इकोनॉमी' की कोशिशों को बड़ा धक्का लगा है क्योंकि नकदी अब भी कालेधन का प्रमुख स्त्रोत है।

सर्वे के अनुसार 39 प्रतिशत लोगों ने नकदी में घूस देने की बात मानी। करीब 25 प्रतिशत ने दलाल के माध्यम से और एक प्रतिशत ने अन्य माध्यम से घूस देने की बात मानी। इधर, 34 प्रतिशत ने कहा कि राज्य द्वारा भ्रष्टाचार नियंत्रण के कदम उठाए गए लेकिन वे प्रभावी नहीं थे।

बढ़ गई रिश्वत देने वालों की संख्या

देश में घूस देकर काम कराने वालों की संख्या पिछले एक वर्ष में 11 प्रतिशत बढ़ गई है। इस साल 56 फीसदी लोगों ने माना कि उन्होंने अपना काम कराने के बदले रिश्वत दी। जबकि पिछले साल ऐसा 45 फीसदी लोगों ने ही माना था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण 'इंडिया करप्शन सर्वे 2018' में यह खुलासा हुआ है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स की ओर से आयोजित इस सर्वे में देश के 215 शहरों में पचास हजार लोगों की 1.6 लाख प्रतिक्रियाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में 33 फीसदी महिलाएं भी थी। 13 राज्यों से मिले सर्वे के नतीजों के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडू में भ्रष्टाचार सबसे अधिक है। गुजरात, केरल और आंध्रप्रदेश में सबसे कम शिकायतें मिलीं। नए कानून के अनुसार रिश्वत देने पर कारावास की सजा और जुर्माने के प्रावधान का भी लोगों में डर नहीं है। सर्वे में 23 फीसदी लोग मानते हैं कि यह कानून प्रभावहीन होगा। *(रा.प., 12.10.18)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
कोटा	ज्योति चौरसिया	पटवारी, भैंसरोड़गढ़ पंचायत, रावतभाटा क्षेत्र	10,000	*रा.प., 06.10.18*
अजमेर	दीपेश शर्मा	लिपिक, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम) कार्यालय	15,000	*दै.भा., 12.10.18*
अजमेर	प्रो. सतीश अग्रवाल	पूर्व विभागाध्यक्ष, महर्षी दयानन्द सरस्वती विश्व विद्या.	50,000	*रा.प., 17.10.18*
भरतपुर	महावीरसिंह आसीवाल	उपायुक्त (प्रतिकरांवचन), वाणिज्यिक कर विभाग	50,000	*रा.प. एवं दै.न., 19.10.18*
बांसवाड़ा	हंस राज मीणा	प्राचार्य, सेंडनानी आदर्श स्कूल गांगड़तलाई	30,000	*रा.प., 23.10.18*
अलवर	शायर सिंह	इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, अलवर	1,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 23.10.18*
जोधपुर	संतोष भाटी नारायण लाल	सरपंच, रानीकला गांव, पाली शिक्षक, पति संतोष भाटी	10,000	*रा.प., 04.11.18*
उदयपुर	गमेर लाल रैगर	प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्रा. विद्यालय, टेकरी	8,500	*रा.प., 14.11.18*
उदयपुर	महावीर जैन प्रकाश भाणावत	अधिशासी अभियंता, कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर सहायक अभियंता, कृषि विपणन बोर्ड, उदयपुर	1,43,000	*रा.प., 16.11.18*
भीलवाड़ा	बजीर खां	अनुबंधित लिपिक, अजमेर डिस्कॉम बनेड़ा, भीलवाड़ा	15,000	*रा.प., 21.11.18*
बारां	सत्यनारायण सिंह	थानाधिकारी, सीसवाली थाना, बारां	20,000	*दै.भा. एवं रा.प., 23.11.18*
दौसा	छुट्टन लाल मीना शुगर बाई	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च मा. विद्यालय, रलावता पत्नी, छुट्टन लाल मीना	15,000	*रा.प., 27.11.18*
जयपुर	अभिषेक कुमार सुरेन्द्र पाल	इंस्पेक्टर, आयकर विभाग, जयपुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आयकर विभाग, जयपुर	10,000	*रा.प., 11.12.18*
जोधपुर	लूणा राम	हेड कांस्टेबल, बोरानाडा थाना, जोधपुर	22,000	*रा.प., 12.12.18*
राजसमंद	रमेश चन्द्र चौरड़िया शचींद्र कुमार शर्मा	एईएन, समग्र शिक्षा अभियान ब्लाक रेलमगरा जेईएन, समग्र शिक्षा अभियान ब्लाक रेलमगरा	34,000	*रा.प. एवं दै.न., 20.12.18*

छोटे उद्योगों को एक करोड़ तक ऋण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छोटे उद्योगों को तुरंत और सस्ता ऋण देने, निरीक्षकों से मुक्ति प्रदान करने, सरकारी कंपनियों में 25 प्रतिशत अनिवार्य खरीद तथा निर्यात कारोबारियों को ब्याज में पांच प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है।

मोदी ने दिवाली के मौके पर 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग-सहयोग एवं संपर्क' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे उद्यमियों को एक करोड़ रुपए तक के ऋण अब मात्र 59 मिनट में स्वीकृत होंगे और उस पर दो फीसदी की ब्याज में छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने उनके हक में 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। *(दै.न., 03.11.18)*

किसान नहीं जानते एमएसपी क्या हैं?

राज्य का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भंवर में उलझकर चक्कर ही खाता रहा है। सरकार हर बार एमएसपी बढ़ाकर किसान को सपने दिखाती है मगर 30 प्रतिशत से ज्यादा खरीद कभी कर ही नहीं पाती। क्योंकि न तो सरकार के पास उत्पादन के अनुपात में गोदाम है और न ही सरकारी खरीद का सशक्त तंत्र। ऐसे में करीब 70 प्रतिशत किसान कम कीमत पर बाजार में अपनी उपज बेचकर घाटा खाने को मजबूर रहते हैं।

हालात यह हैं कि हर सीजन में ज्यादातर कृषि उत्पाद एमएसपी से करीब 25 से 35 फीसदी नीचे दाम पर घरेलू मंडियों में बिक रहे हैं। सरकार को भंडारण की व्यवस्था व कृषि जिंसों की खरीद के लिए सशक्त तंत्र विकसित करना चाहिए। *(रा.प., 05.10.18)*

मीडिया सत्ता से सवाल पूछे

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग जनता से सीधे संपर्क में होते हैं। लिहाजा जनता के हित में मीडिया को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने चाहिए। यह लोकतांत्रिक समाज की रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने फर्जी खबरों को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है।

पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि अफसरशाही विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। इसमें जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। नौकरशाही को विकास में योगदान के लिए अनुकूल बनाना होगा और कार्य में लचीलापन लाना होगा ताकि बेहतर नीतियां बनाई जा सकें।

(रा.प., 20.11.18)

हमारी सरकार गुड गवर्नेंस देगी

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पांच साल तक राजस्थान में कुशासन रहा है। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार गुड गवर्नेंस देगी। किसानों के कर्जे माफ होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जन समस्याओं की सुनवाई होगी।

उन्होंने कहा कुशासन के दौर में प्रदेश में रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो, आदिवासी क्षेत्रों में ब्रॉडगेज, हाडोती में डेम आदि योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। योजनाएं बंद होने से लोगों में भारी गुस्सा था। पांच साल में वसुंधरा राजे किसी से मिली ही नहीं। यहां तक कि जनता, विधायकों, मंत्रिमंडल के साथियों से भी नहीं मिलती थीं। एक गुस्सा था, उनके प्रति जो खुलकर सामने आया और अब कांग्रेस की सरकार बन रही है। *(रा.प., 15.12.18)*

जलवायु परिवर्तन से खेती पर संकट

भारत के 151 जिलों की फसलें, पेड़-पौधे और पशु जलवायु परिवर्तन के कारण अति संवेदनशील हालत में पहुंच चुके हैं। यह देश के कुल जिलों का करीब 20 फीसदी है।

कृषि मंत्रालय से जुड़े संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) की वार्षिक समीक्षा में यह चिंता जताई गई है। खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि फसलों के उत्पादन के बारे में अनुमान भी गलत साबित हो रहे हैं।

हालांकि सरकार ऐसे कई कार्यक्रम चला रही है, जिससे खेती में हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन से न केवल तापमान बढ़ा है बल्कि बारिश भी कम हो रही है। इससे सिंचाई तंत्र भी खराब हुआ है। *(रा.प., 19.11.18)*

केंद्रीय कृषि योजनाओं पर माथापच्ची

हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में हुई भाजपा की हार के पीछे किसानों की नाराजगी को एक बड़ा कारण माना जा है। इसे देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय में सरकार की योजनाओं को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है।

कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसानों के कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। अधिकारियों से सभी राज्यों में किसान संबंधी योजनाओं में खर्च हुए धन का ब्योरा भी जुटाने को कहा गया है।

(रा.प., 17.12.18)

प्रदेश में किसानों के कर्ज हुए माफ

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी कर्जमाफी की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सहकारी बैंकों से लिए गए सभी अल्पकालीन ऋण माफ होंगे। इसके अलावा जो किसान राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व अन्य बैंकों से लिया कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

किसानों को 30 नवम्बर 2018 तक लिए गए कर्ज पर यह राहत मिलेगी। भाजपा सरकार की ओर से माफ किए गए ऋण भी इसमें शामिल होंगे। कर्जमाफी का लाभ ले चुके वे किसान भी लाभान्वित होंगे जिनका कर्ज पचास हजार रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्ज माफी से सरकार के खजाने पर 18 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसमें भाजपा सरकार के समय माफ किए गए छह हजार करोड़ रुपए भी शामिल हैं। *(रा.प., 20.12.18)*

अक्षय ऊर्जा में 76 फीसदी लक्ष्य हासिल करेगा भारत

भारत 2022 तक 1,75,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य का करीब 76 प्रतिशत तक ही हासिल कर सकता है क्योंकि इसके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। वूड मैकेन्जी ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। दुनिया की प्रमुख शोध और परामर्श कंपनी ने रिपोर्ट में कहा 'लागत में उल्लेखनीय कमी के बावजूद 2022 तक 76 प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल होने की उम्मीद है।' रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बावजूद यह उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

वूड मैकेन्जी के सौर विश्लेषक आर.श्रेष्ठ ने कहा कि भारत में अक्षय ऊर्जा उद्योग के समक्ष कई चुनौतियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार उद्योग की बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। वूड मैकेन्जी ने कहा कि पवन और सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के मुकाबले दोगुना होकर इस साल 61,000 मेगावाट पहुंच गई है। *(न.नु., 16.10.18)*

नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन

सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की योजना पर आगे बढ़ रही है और इसके तहत 26000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के लिए निविदाएं पहले ही मंगाई जा चुकी हैं।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास ऐजेंसी (इरेडा) के चेयरमैन के. एस. पोपली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत अगले पांच साल में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से 50000 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि सौर सेल की क्षमता बढ़ रही है और हम अगले कुछ सालों के दौरान इसके वाणिज्यिक उत्पादन को देखेंगे। इससे संबंधित नीतियों पर भी गौर किया जा रहा है। *(न.नु., 19.11.18)*

अब हर माह मिलेंगे बिजली बिल

प्रदेश की राजधानी जयपुर के उपभोक्ताओं को अब हर माह बिजली के बिल मिलेंगे। जनवरी से ऑन स्पॉट बिलिंग शुरू हो जाएगी। इसमें मीटर से रीडिंग लेने के साथ ही बिल मिल जाएगा। बिल जारी करने की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए मीटर रीडर के पास हैंडल्ड डिवाइस होगी। जयपुर डिस्कॉम ने इस संबंध में संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। शहर में 8.60 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं।

जयपुर डिस्कॉम से जुड़े 13 शहरों में से केवल जयपुर ही बचा था। उधर, डिस्कॉम अधिकारियों ने दावा किया है कि बिलिंग प्रक्रिया बदली है लेकिन इससे उपभोक्ता पर किसी भी तरह का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। *(रा.प., 20.12.18)*

ऊर्जा बचत लक्ष्य से 30 फीसदी ज्यादा

प्रथम चक्र के तहत ऊर्जा की बचत की जानकारी देते हुए केंद्रीय रिनिवेबल ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा ने कहा कि परफॉर्म एच्चीव एंड ट्रेड (पीएटी) के प्रथम चक्र में सरकार ने लक्ष्य को अर्जित करते हुए 9500 करोड़ रुपए का बचत लक्ष्य अर्जित किया है।

उन्होंने कहा कि पीएटी प्रथम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 30 प्रतिशत अधिक बचत अर्जित की गई है। इस लक्ष्य को अर्जित करके देश ने 8.67 मि.टन तेल के बराबर बचत अर्जित की है जबकि लक्ष्य 6.867 मि.टन का निर्धारित किया गया था। सरकार कुल 19 एमटीओई का लक्ष्य आगामी 2 पीएटी साईकिल में अर्जित कर लेगी। रिपोर्ट के अनुसार पेपर पर पल्प उद्योग ने अब तक की सर्वाधिक बचत अर्जित की है जो बढ़कर 0.29 एमटीओई के लगभग है। उन्होंने कहा कि स्टील व इस्पात उद्योग ने 2.10 एमटीओई के बराबर बचत अर्जित की है जो कुल बचत के लक्ष्य से 41 प्रतिशत अधिक है। *(न.नु., 03.10.18)*

सभी घरों में हो गए बिजली कनेक्शन

प्रदेश में पहली बार जयपुर डिस्कॉम के 12 जिलों में सभी मकानों में बिजली कनेक्शन हो गए हैं। सौभाग्य स्कीम के तहत पिछले एक साल में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर 12 जिलों में 6 लाख 21 हजार 609 घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं। डिस्कॉम के सभी सब-डिविजन कार्यालयों में 16 अक्टूबर से पहले हुए आवेदनों के बिजली मीटर लगा कर कनेक्शन कर दिए गए है। जयपुर डिस्कॉम के सीएमडी आर.जी. गुप्ता की सख्त मॉनिटरिंग से यह लक्ष्य हासिल हुआ है।

आर.जी. गुप्ता ने बताया कि डिस्कॉम में सौ फीसदी घरेलू कनेक्शन हो गए हैं। स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 अक्टूबर 2017 से आवेदन लेने व कनेक्शन देना शुरू किया था। डिस्कॉम के इंजीनियर व कर्मचारियों के टीम वर्क से यह लक्ष्य कम समय में पूरा हो पाया है। *(दै.भा., 01.12.18)*

सवा लाख कृषि कनेक्शन पेंडिंग

प्रदेश में किसानों को समय पर बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छह साल पहले यानी जनवरी 2012 से भी पहले कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके और डिमांड राशि जमा कराने के बावजूद प्रदेश के तीनों डिस्कॉम में सवा लाख से भी ज्यादा बिजली कनेक्शन बकाया हैं। जबकि किसानों से एक कनेक्शन पर 20 से 50 हजार रुपए तक लिए जा चुके हैं।

किसानों द्वारा राशि जमा कराने के बाद भी कृषि कनेक्शन नहीं मिलना सिस्टम की मॉनिटरिंग पर सवाल खड़ा कर रहा है। जोधपुर डिस्कॉम में सबसे ज्यादा 47 हजार, जयपुर डिस्कॉम में 42 हजार और अजमेर डिस्कॉम में 39 हजार खेतों को बिजली कनेक्शन देना बकाया है। *(दै.भा., 06.10.18)*

काम की धीमी गति : अटके कनेक्शन

प्रदेश के हर घर में उजाला करने के लिए केन्द्र सरकार ने 2800 करोड़ रुपए दीनदयाल विद्युतीकरण और 1400 करोड़ रुपए की सौभाग्य योजना लागू की, लेकिन सौभाग्य स्कीम के सर्वे की मानें तो प्रदेश में करीब 7.65 लाख घरों में बिजली नहीं है। इन सभी को कनेक्शन दिए जाने हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत जोधपुर डिस्कॉम में 83 हजार, अजमेर डिस्कॉम में 89 हजार कनेक्शन अटके पड़े हैं। जयपुर डिस्कॉम में दौसा व भरतपुर के अलावा ज्यादातर कनेक्शन हो चुके हैं और करीब 4500 कनेक्शन बकाया है। *(रा.प., 05.11.18)*

जल प्रबंधन पर लगा प्रश्न चिन्ह

राजस्थान में सूखते हुए जल के स्त्रोत जल प्रबन्धन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। यहां सबमर्सिबल पंपों से भूमि के निचले स्तर तक जल का दोहन हो रहा है। कृषि की वैज्ञानिक जानकारी का अभाव होने से किसान 15 फीसदी पानी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं।

जल संकट से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने के साथ-साथ समुचित भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। वर्षा जल के संरक्षण एवं संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए पुख्ता कार्यवाही करनी होगी। प्रदेश में जल स्वावलंबन अभियान सार्थक परिणाम दे रहा है।

(दै.न., 03.11.18)

जल संरक्षण शुल्क का प्रावधान

केंद्र सरकार ने भूमिगत जल का दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत नियामक तंत्र सुनिश्चित करने के वास्ते भूजल इस्तेमाल को लेकर नियमों में संशोधन संबंधी एक अधिसूचना जारी की है। इसमें की गई व्यवस्था अगले वर्ष जून से प्रभावी होगी। नई व्यवस्था में जल संरक्षण शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए भूमिगत जल के इस्तेमाल को लेकर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों में सुधार करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। *(दै.न., 14.12.18)*

पेयजल उपभोक्ताओं पर दोहरी मार

जयपुर शहर में पेयजल कटौती से परेशान उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। कटौती के कारण पानी तो 30 प्रतिशत कम मिल रहा है मगर बिल उतनी ही राशि का थमाया जा रहा है। सवाल उठता है कि जलदाय विभाग मीटर से रीडिंग ले रहा है या औसतन के आधार पर लोगों को बिल भिजवा रहा है।

लोगों ने इसकी जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत की पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शहर में 4.75 लाख उपभोक्ता है, जिनके मीटर लगा हुआ है। गौरतलब है कि बीसलपुर बांध में पानी की कमी के चलते शहर में 28 अगस्त से 30 प्रतिशत तक पेयजल की कटौती की जा रही है। लोगों को निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। शहर के कई इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। *(रा.प., 07.11.18)*

गांवों में ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जल संरक्षण के क्षेत्र में बनाए गए ड्रीम प्रोजेक्ट जल स्वावलंबन अभियान को राज्य सरकार के अफसर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह अमलीजामा नहीं पहना सके। जल संरक्षण के कई बड़े कार्य बजट घोषणा में शामिल तो हुए मगर उनकी क्रियान्विति अभी तक अटकी हुई है।

जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण में अभी भी 25 हजार से ज्यादा काम अधूरे पड़े हैं। हालांकि ज्यादातर काम शुरू हो चुके हैं मगर उनको पूरा करने की रिपोर्ट अभी तक पंचायतीराज विभाग को नहीं मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के तीसरे चरण में 4240 गांवों में एक लाख 40 हजार कार्य कराने का निर्णय लिया गया था। उनमें से 26 हजार 714 काम अभी तक पूरे नहीं किए जा सके।

(दै.न., 24.12.18)

पम्प हाउस पर सौर ऊर्जा अनिवार्य

जलदाय विभाग अब पेयजल आपूर्ति के साथ बिजली उत्पादन भी करेगा। अब जो भी नया पम्प हाउस बनेगा, उस पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना जरूरी होगा। इसके बिना पेयजल आपूर्ति शुरू ही नहीं की जाएगी। जयपुर शहर के खानागोरियान व जामडोली में 4 पम्प हाउसों से इसकी शुरुआत होगी।

हर प्लांट पर हर दिन 7.50 किलोवॉट बिजली बनेगी। यानी चारों पम्प हाउसों से रोजाना 128 यूनिट बिजली मिलेगी। इसका उपयोग पम्प हाउस संचालन में ही होगा। बिजली बची तो डिस्कॉम को दी जा सकेगी। विभाग ने पेयजल लाइन बिछाने, टंकी व पम्प हाउस के निर्माण कार्य संबंधी अनुबंध में ही उक्त शर्त शामिल कर दी है। *(रा.प., 10.10.18)*

पानी की कमी पर हाईकोर्ट चिंतित

हाईकोर्ट ने प्रदेश में पानी की कमी और इसके लिए राज्य सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं होने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि पानी को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है और वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर बोरिंग खोदे जा रहे हैं। जयपुर और पूरे प्रदेश में कितने बोरिंग है किसी को पता नहीं हैं। बीसलपुर में पानी नहीं है अब पानी कहां से आएगा, सब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ऐसे में पानी चोरी होने पर आजकल एफआईआर भी दर्ज होने लगी है।

न्यायाधीश एम.एन.भंडारी व बी.एल. शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के जल बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए की। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को राजस्व विभाग को दिए गए निर्देश के संबंध में पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। *(दै.भा., 14.12.18)*

पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं लोग

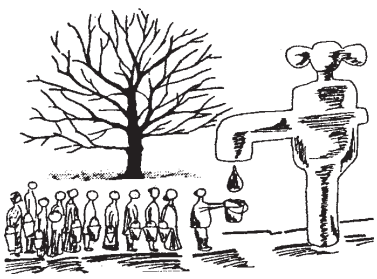

पेयजल किल्लत से जूझते जयपुर शहरवासियों के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। जलदाय विभाग ने शहर में बंद पड़े ट्यूबवैल से अतिरिक्त पानी लेने का काम शुरू किया, लेकिन कई ट्यूबवैल में से तो पानी ही नहीं मिल पाया। कुछ ट्यूबवैल की 400 फीट से ज्यादा तक खुदाई की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।

भूजल विशेषज्ञों के मुताबिक भूजल स्तर हर साल औसतन 0.5 मीटर गिर रहा है। भूजल नीचे गिर जाने के कारण ऐसे हालात पनपे हैं। अभी बीसलपुर से 350 एमएलडी व मौजूदा ट्यूबवैल से करीब 70 एमएलडी पानी लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिन ट्यूबवैल से पानी नहीं मिल पाया है, उन्हें वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। बारिश में नालों में बहने वाले पानी को भूगर्भ में ले जाया जाएगा। *(रा-.प., 31.10.18)*

कृषि योजनाओं में महिलाएं हों लाभार्थी

कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण योजनाओं में 30 फीसदी बजटीय आवंटन महिलाओं के लिए करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। इस बारे में राज्यों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। लोकसभा में यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा 'कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग 30 फीसदी बजटीय आवंटन के जरिए कृषि में महिलाओं की भूमिका को पहचान देने और मुख्यधारा में लाने को उच्च प्राथमिकता देता है।'

रुपाला ने कहा कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं के तहत कम से कम 30 फीसदी लाभार्थी महिला किसान हों। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और उनके सशक्तिकरण और अवसरों के विस्तार करने के मकसद से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। *(न.नु., 19.12.18)*

महिलाओं को मिला कम मौका

देश की 71 फीसदी कंपनियों में 10 फीसदी से भी कम महिलाकर्मी हैं। सिर्फ एक प्रतिशत कंपनियां ही उच्च पदों पर महिला को मौका देती है। उच्च पदों पर 40 प्रतिशत कंपनियों की पंसद कोई पुरुष ही होता है। सिर्फ 2.4 प्रतिशत कंपनियों में महिला व पुरुष कर्मियों के बीच 50-50 का अनुपात है। यह नतीजा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की एक अध्ययन रिपोर्ट से निकल कर सामने आया है।

डब्ल्यूईएफ ने कार्यस्थल पर जेंडर गैप का पता लगाने के लिए भारत में यह अध्ययन किया है। 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' नाम की इस रिपोर्ट में एक तिहाई कंपनियां तो ऐसी हैं, जहां स्टाफ में कोई महिला है ही नहीं।

सर्वे में जब कंपनियों से पूछा गया कि वो उच्च पदों पर महिला व पुरुष में से किसे लेना पसंद करेंगे तो हर 10 में से एक कंपनी ने ही महिला का नाम लिया। अध्ययन में देश की कुल 770 कंपनियों को शामिल किया था।

(दै.भा., 10.10.18)

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ है सही कदम

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि तथा किशोरी योजना जैसे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा है कि इससे देशवासियों की सोच में बदलाव आ रहा है।

उन्होंने फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसायटी ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ लोग अभी भी बेटियों के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। बेटियों पर कई बंदिशें होने के बावजूद वह समाज में नित नए आयाम रच रही हैं।

उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों से आह्वान किया कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए महिलाओं और वंचित वर्ग को स्वास्थ्य शिक्षा और संबंधित सहूलियतें पहुंचाना आपके कंधों पर है। *(दै.न., 07.10.18)*

बच्चे हो रहे हैं कुपोषण के शिकार

अनेक सरकारी योजनाओं और मोटे खर्चे के बावजूद राज्य में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कुपोषण दूर करने के लिए राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पोषाहार के साथ दूध पिलाने की योजना है। इन योजनाओं पर सालाना हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद धरातल पर सही परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं।

केंद्र सरकार के क्लिनीकल, मानवशास्त्रीय व बायो कैमिकल (सीएबी) सर्वे के अनुसार प्रदेश में 23 फीसदी बालक और 22.3 फीसदी बालिकाएं कुपोषण से ग्रसित हैं। पांच साल से कम आयु के 12.6 फीसदी बालक और 11.7 फीसदी बालिकाएं अतिकुपोषित हैं। पांच से 18 साल की आयु की 11.6 फीसदी लड़कियां व 17.2 फीसदी लड़के अतिकुपोषण के शिकार हैं। *(रा.प., 14.11.18)*

अपने घर में ही सुरक्षित नहीं महिलाएं

आमतौर पर माना जाता है कि महिलाओं के बिना कोई घर मुकम्मल नहीं होता। मगर कड़वी हकीकत यह है कि महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह उनका घर ही है। दुनियाभर में पिछले साल जितनी महिलाओं की हत्या हुई, उनमें से आधे से ज्यादा मामलों में गुनहगार उनके सबसे करीबी सहयोगी या परिवार के सदस्य ही थे। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में हुआ है। हकीकत यह है कि पुरुषों से रिश्तों में असंतुलन होना इस हिंसा की वजह है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में हर एक घंटे में छह महिलाओं की उनके ही करीबी हत्या कर देते हैं। वर्ष 2017 में हर दिन 137 महिलाओं की उनके परिवार के सदस्यों ने ही हत्या कर दी।

रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ होने वाले इन अपराधों को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत है। साथ ही पुलिस और कानून व्यवस्था में सामंजस्य बेहतर करने का सुझाव दिया गया है। *(रा.प., 27.11.18)*

नए राशन कार्ड में महिला ही मुखिया

अब घर के मुखिया पुरुष की जगह घर की सबसे उम्रदराज महिला होगी। खाद्य सुरक्षा की धारा 13 में महिला को यह अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के तहत बनने वाला राशन कार्ड घर की महिला मुखिया के नाम से बनाया जाएगा। राशन कार्ड में मुखिया के रूप में महिलाओं का नाम दर्ज करने का अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है।

खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग की तरफ से जयपुर जिले में राशन कार्ड बनाए जाने हैं। मौजूदा प्रचलन वाले राशन कार्डों की मियाद खत्म होने वाली है। अब नए राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर बनेंगे। परिवार में यदि कोई महिला 18 साल की नहीं है तो पुरुष को गृहस्थ मुखिया बनाया जाएगा। लेकिन 18 साल की होते ही युवती का नाम घर की मुखिया के रूप में दर्ज हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वे फॉर्म पूरा करेंगे।

(दै.भा., 26.12.18)

सड़क सुरक्षा

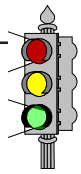

योजनाओं के क्रियान्वयन से कम हुई दुर्घटनाएं

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में बना सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में कारगर साबित हो रहा है। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागृत करने और प्रकोष्ठ की ओर से किए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन से दो साल में 1006 दुर्घटनाओं में कमी हुई है। प्रकोष्ठ तीन साल में करीब 100 से भी ज्यादा सड़क सुरक्षा की योजनाएं लागू कर चुका है। यह सब सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा नीति, सड़क सुरक्षा फंड के गठन के साथ नियमित रूप से लोगों को रोड सेफ्टी पर जागृत करने से ही संभव हो पाया है। लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागृत करने के लिए हर साल 82 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान रखा गया है।

योजनाओं के तहत परिवहन विभाग ने मुख्य रूप से स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम बजट के माध्यम से शामिल किया गया, दो साल में 901 ब्लैक स्पॉट्स दुरुस्त किए गए, साढ़े तीन हजार किलोमीटर की सड़कों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट की गई, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों का चालान किया गया, सड़क सुरक्षा पर काम करने के लिए 70 स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) का गठन किया गया है। हर साल 2 अक्टूबर और 27 जनवरी को 9894 ग्राम पंचायतों पर जन जागृत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टरों, इंजीनियरों व परिवहन अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई है। समय-समय पर ऐसी कई योजनाओं के क्रियान्वयन से सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सका है। *(दै.भा., 05.11.18)*

वित्तीय सेवाएं

बैंकों के खिलाफ शिकायतों में हुई बढ़ोतरी

बैंकों की खराब सेवाओं के खिलाफ शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों की खराब सेवाओं के खिलाफ 2008 तक देश भर में प्रतिदिन 132 शिकायतें दर्ज होती थी जो 31 मार्च 2018 तक बढ़कर 309 शिकायतें हो गई।

सूचना के अधिकार(आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है। इस जानकारी के मुताबिक पिछले दस सालों में रोजाना आने वाली शिकायतों का आंकड़ा करीब 134 फीसदी बढ़ा है। इसमें भी सर्वाधिक शिकायतें 2008-2016 के बीच सालाना तौर पर बढ़ी। इस दौरान सालाना तौर पर 44 फीसदी की दर से ग्राहकों की शिकायतें बढ़ी। आरटीआई के मुताबिक पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा शिकायतें 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी और 2016 में नोटबंदी के दौरान दर्ज की गई। हालांकि शिकायतों के निपटारे के लिए आरबीआई के 21 अधिकारियों की विशेष टीम ने करीब एक फीसदी शिकायतों को ही वैध माना। अन्य शिकायतों को या तो बैंकिंग लोकपाल ने अस्वीकार कर दिया या शिकायतकर्ताओं ने वापस ले लिया। सबसे अधिक शिकायतें एटीएम से जुड़ी हुई हैं। *(रा.प., 10.10.18)*

पर्यावरण

जानलेवा हो रही है जयपुर की हवा

सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अनियंत्रित वाहन दबाव और उससे बढ़ रहे प्रदूषण के कारण कई जानलेवा बीमारियां बढ़ रही है। इससे यहां रहने वाले लोगों की औसत उम्र कम हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर तय मानकों से ढ़ाई गुना अधिक प्रदूषित है। वहीं, हाल ही प्रदूषण को लेकर सामने आई अमरीकी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में माना गया है कि जयपुर में रहने वाले लोगों की औसत आयु प्रदूषण के कारण लगातार कम हो रही है। इसके लिए माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (पीएम) 2.5 और पीएम 10 को मापा गया। मानकों के अनुसार पीएम 2.5 वायु में 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। देश में प्रदूषण मानक के अनुसार यह 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जयपुर में यह 100 मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में एक दशक के दौरान घर के अंदर और बाहर प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें चौगुनी बढ़ जाएंगी।

जयपुर में अस्थमा, एलर्जी व श्वास रोग विशेषज्ञों की मानें तो, शहर में चारदीवारी और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास सर्वाधिक प्रदूषण है। इसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण से धूल के कण फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इससे हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर व अस्थमा तेजी से बढ़ता है। प्रदूषण का बड़ा कारण वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फरडाइ ऑक्साइड का बढ़ना है। जयपुर में सल्फरडाइ ऑक्साइड का स्तर 25 से 45 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच रहा है, जो काफी अधिक है। *(रा.प., 21.11.18)*

जन स्वास्थ्य

बीमा कंपनीयों को उठाने होंगे हर बीमारियों के खर्च

जल्द ही बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा लेने के बाद होने वाली सभी बीमारियों का खर्च उठाना होगा। भले ही वह बीमारियां कंपनी के स्थाई रूप से अपवर्जित (बीमा से बाहर) बीमारियों की सूची में हों। अब बीमा कंपनियां केवल उन्हीं अपवर्जित बीमारियों के दावे देने से इनकार कर सकती है, जो बीमा खरीदने के समय बीमाधारक को पहले से हों। बीमाधारक और बीमा के दायरे में आने वाले उसके परिजनों को बीमा खरीदने के बाद कंपनी की वर्जित सूची में शामिल कोई बीमारी हो जाती है (जो उसे बीमा लेते वक्त न हो) तो कंपनी को उसके इलाज के लिए भर्ती होने पर अस्पताल का खर्च देना होगा। यह सिफारिश बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की एक कार्यसमिति ने की है।

सिफारिश के अनुसार जलजनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि से होने वाली मौत को हादसे में होने वाली मौत की बजाय बीमारी से मौत माना जाएगा। वहीं सांप या बिच्छु के काटने या किसी जंगली जानवर के हमलों से घायल होने या मौत होने को हादसा माना जाएगा। बीमा के दायरे की बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली नई तकनीक और दवाओं को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य प्रोद्योगिकी आकलन समिति बनाई जाएगी। *(रा.प., 05.11.18)*

उपभोक्ता फैसले

हाउसिंग बोर्ड 36 साल पुरानी शर्तों पर मकान दें

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में नवरतन नाहटा व गौरव नाहटा ने अपने वकील आदित्य मित्रुका के जरिए जयपुर स्थित राजस्थान आवासन मंडल के खिलाफ परिवाद दायर किया। मित्रुका ने आयोग को बताया कि आवासन मंडल की योजना में 1982 में आवेदन किया गया था और परिवादीगण को मकान आरक्षण की सूचना भी मिल गई। इस पर उन्होंने 20 हजार रुपए का चैक भी जमा करार दिया। लेकिन मकान आवंटन नहीं हुआ। आवासन मंडल ने स्ववित्त पोषित योजना के तहत सहमति नहीं देने का हवाला देते हुए उनका आवंटन ही निरस्त कर दिया। उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष परसराम मोरदिया को इस बारे में ज्ञापन दिया तो तथ्यों के आधार पर पंजीयन बहाल कर दिया गया। लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के पंजीयन बहाली के आदेश को निरस्त कर दिया। मित्रुका ने आयोग को बताया कि इस निर्णय के खिलाफ यह परिवाद दायर किया गया है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने परिवादी का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही को सही नहीं माना। आयोग ने आवासन मंडल को न केवल 36 साल पुरानी वरीयता के आधार पर मकान देने, बल्कि मानसिक संताप व परिवाद खर्च के रूप में साढ़े पांच लाख रुपए का हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है। आयोग ने इन सबके साथ परिवाद पेश करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज भी देने का निर्देश दिया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 02.09.18)*

संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल पर 50 लाख का हर्जाना

सीकर जिले के खंडेला निवासी शिवदयाल पालीवाल ने राज्य उपभोक्ता आयोग में संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल के खिलाफ परिवाद दायर किया। उन्होंने परिवाद में आयोग को बताया कि उनके 30 वर्षीय पुत्र संजय को बुखार होने पर दुर्लभजी अस्पताल में दिखाया। यहां डॉ. अनुराग गोविल ने कई जांचें कराई पर इन सबकी रिपोर्ट सामान्य आई। संजय को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। इस बीच कई अन्य जांचें भी हुई लेकिन रिपोर्ट सामान्य बताई गई। कुछ दिन बाद ही संजय को सांस लेने में तकलीफ पैदा हो गई तो फेफड़े में संक्रमण बताकर आईसीयू में भर्ती कर लिया। इसके बाद बिना जांच के स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती किया। उन्होंने बताया कि एण्डोस्कोपी के दौरान उनके पुत्र की श्वास नली में इंजरी हो गई, इससे खून फेफड़ों में चला गया और लापरवाही बरतने से संजय की मौत हुई।

मामले की सुनवाई पर आयोग ने माना कि एण्डोस्कोपी की रिपोर्ट किसी अन्य मरीज की थी, जिसे परिवादी के पुत्र की रिपोर्ट बताई गई। इलाज में लापरवाही से संजय की मौत हुई। आयोग ने संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल और डॉ. अनुराग गोविल को आदेश दिया कि वह संजय के माता-पिता को 50 लाख रुपए का हर्जाना और परिवाद की तारीख से हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज अदा करें।

(दै.भा. एवं दै.न., 15.11.18)

कंज्यूमर प्रॉटेक्शन को सरकार ने दी धार

ग्राहकों को और अधिक अधिकार देने के लिए तीन दशक पुराने कानून को बदला जा रहा है। लोकसभा में नया उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 पास हो गया है और इसे अब राज्यसभा में भेजा जाएगा। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह लेगा। यह देश के उपभोक्ता अधिकारों को लेकर क्रांतिकारी साबित हो सकता है। इसके तहत उपभोक्ताओं और एजेंसियों को मौजूदा कानून के मुकाबले बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान हो। उन्होंने कहा कि इसमें राज्यों के अधिकारों का पूरा खयाल रखा गया है और इसमें किसी तरह का दखल नहीं होगा। पासवान ने कहा कि यह कानून 1986 में बना था, तब से स्थिति में इतना बदलाव आ गया लेकिन कानून पुराना ही था। इसलिए नया विधेयक लाने का निर्णय किया गया। बिल में सेंट्रल कंज्यूमर प्रॉटेक्शन अथॉरिटी के गठन का भी प्रस्ताव है।

(न.नु., 21.12.18, 24.12.18)

उपभोक्ता विवादों का शुल्क घटाया

केंद्र सरकार ने पांच लाख रुपए तक उपभोक्ता विवादों के लिए शुल्क समाप्त कर दिया है, जबकि पहले केवल बीपीएल के लिए शुल्क नहीं लगता था। अब पांच से 10 लाख रुपए तक के विवादों पर 200 रुपए और 10 से 20 लाख तक के विवादों के लिए 400 रुपए शुल्क देना होगा।

अब 20 लाख रुपए तक का दावा करना है तो आप जिला उपभोक्ता मंच जा सकते हैं। एक करोड़ रुपए तक का मामला है तो राज्य उपभोक्ता आयोग में जाना होगा। राज्य आयोग में जिला मंच के फैसलों की अपील भी होती है। एक करोड़ रुपए से अधिक का विवाद है तो सीधे राष्ट्रीय आयोग जाना होगा। *(रा.प., 05.11.18)*

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।
'कट्स' इन्टरनेशनल एक गैर-लाभकारी संस्था है तथा सशुल्क समाचारों/लेखों की सूची केवल सूचना एवं अध्ययन के लिए है।